मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

ए एस आई चुलबुल पांडे के समर्थन में खड़े उच्चाधिकारी — 3

मोदी के 'अच्छे दिनों' का आगाज़ परजीविओं पर चुप्पी : शोर करने के बहाने कई! — 4

भाजपा के निर्देशन में डी.यू व यू जी सी का ड्रामा रिलायंस पर सरकार की मेहरबानियां — 6

ई एस आई सी रीजनल बोर्ड की बैठक एक छलावा मात्र — 8

वर्ष 27 अंक 16 फरीदाबाद, मंगलवार, 1-15 जुलाई 2014 फोन : - 9999595632 ₹ 2

विधायक शारदा राठौर का आधार खिसकने लगा

पाले-पोसे पार्षद भाजपा में जाने लगे

सन् 2004 से अब तक लगातार दो बार चुनाव जीत कर क्षेत्र की विधायक रही शारदा राठौर का आधार अब खिसकने लगा है। यही हाल रहा तो टिकट के भी लाले पड़ सकते हैं। गत सप्ताह मुख्यमंत्री की रैलियों में भीड़ न जुटा पाने से वे भी खफ़ा नज़र आये।

मज़दूर मोर्चा, बल्लबगढ ब्यूरो

शारदा राठौर ने आम आदमी पर भरोसा कर, उसे अपना आधार बनाने की बजाय भ्रष्ट प्रॉपर्टी डीलरों को अपना आधार बनाया। ये लोग भ्रष्टाचार, हेराफ़ेरी एवं जात-पात के आधार पर एवं शारदा राठौर के सहयोग से पार्षद बन गये। पार्षद बनने के बाद तथा शरदा राठौर के सहयोग से खूब जम कर घपले किये। अवैध प्लाटिंग एवं अवैध निर्माणों के जरिये करोड़ों के वारे-न्यारे किये। इन पार्षदों में से सबसे पहले साथ छोड़कर भागने वाले थे धरेन्द्र यादव, कमल यादव और राव राम कुमार।

राव राम कुमार ने अपनी उमड़ती महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत 'आप' (आम आदमी पार्टी) में जाने का मन बनाया था। परन्तु लोकसभा चुनावों में उसका खोमचा बिखरता देख तुरन्त भाजपा की ओर मुंह कर लिया और गत माह कृष्णपाल के हाथों विधि-विधान एवं समारोहपूर्वक भाजपा में प्रवेश पा लिया। लिहाजा अब ये भाजपा के वरिष्ठ नेता' हो गये हैं। कल तक हर सांस में जिस विधायक शारदा की स्तुति गाते थे आज उसी को पानी पी-पी कर कोस रहे हैं, तरह-तरह के आरोप लगा रहे हैं। चार साल तक पूरी मौज लेन के बाद आज राव राम कुमार क्षेत्र की दुदर्शा के लिये विधायक को दोषी बता रहे हैं। इतना ही नहीं बाकायदा पर्चे बांट कर जनता को कह रहे हैं ''अगर समस्याएं करनी हैं हल तो राजनीति से कर दो इन्हें बेदखल।'' दूसरे शब्दों में क्षेत्र की तमाम समस्याएं हल करने के लिये अब शारदा की जगह इन्हें बैठा दिया जाये।

ये तीन तो चले गये, चौथे श्रीमानजी राजेन्द्र अग्रवाल जाने को कतई तैयार बैठे है। यदि 28 जून को सूरजकुंड में मोदी की

पाले हुये सांप भी डस लेते हैं

पाठशाला न लगी होती तो यह काम उसी दिन होने वाला था। अब किसी नये 'शुभ' दिन की तलाश है। राजेन्द्र अग्रवाल वार्ड नम्बर 8 से पार्षद हैं। इस क्षेत्र में लगभग सारा बनियावाड़ा आ जाता है। पार्षद बनने के बाद विधायक के सहयोग एवं संरक्षण से इन्होंने प्रापर्टी के धंधे से एक-दो नहीं सैंकड़ों करोड़ के वारे-न्यारे कर लिये हैं। जिस बनियावाड़ा की रिहायशी गलियों में जमीन का भाव बीस हज़ार तक था, वहीं अब दो लाख रुपया प्रति वर्ग गज का हो गया है। कारण यह कि यदि और कोई आम आदमी किसी मकान को खरीद कर उसमें दुकाने बनाये तो वह अवैध और उसे तोड़ने को नगर निगम वाले आ धमकते। लेकिन जब राजेन्द्र बेसमेंट से लेकर तीन-तीन, चार-चार मंजिला शॉपिंग कॉम्पलेक्स बनाये तो वह 'वैध'। बेशक नक्शा पास न हो, कम्पलीशन न हो फ़िर भी लोग विधायक के आशीर्वाद से पार्षद द्वारा बनायी गयी दुकानों को मुंहमांगे दामों पर खरीद लेते हैं। इसी को कहते हैं राजनीतिक सत्ता का प्रभाव। हींग लगे न फ़टकड़ी रंग आये चोखा। अवैध धंधे की कमाई के बूते आज इस पार्षद के पास अनेकों, एक से एक बढिया कारें हैं, निकट के एक गांव हीरापुर में फ़ार्म हाउस है जिसमें निगम की ओर से गैरकानूनी तरीके से दर्जनों वे स्ट्रीट लाइटें लगाई गयी हैं। जो बल्लबगढ की गलियों में लगनी चाहिये थीं। तिगांव रोड पर, अग्रवाल कॉलेज के निकट एक बहुमंजिला अवैध शॉपिंग काम्प्लेक्स तो आज भी निर्माणाधीन है। यदि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त न होता तो नगर निगम वाले कब का इसे धाराशाही कर देते।

अवैध प्रॉपर्टी डीलिंग के अलावा इस पार्षद पर चोरी का माल खरीदने का गंभीर आरोप भी लगा है। पिछले दिनों थाना शहर की आदर्श नगर चौकी ने एक मुकदमें की तफ़्तीश में एक चोर को पकड़ा था। पूछताछ में उसने बताया कि चोरी का कीमती माल-सोने के ज़ेवरात आदि-वह पार्षद अग्रवाल को ही बेचता है। इस पर पुलिस ने इस पार्षद को तलब किया था। जान छुड़ाने के लिये विधायक के राजनीतिक दबाव के साथ-साथ पुलिस को नब्बे हज़ार रुपये भी दियो गये थे। इसके अलावा करीब 6-7 माह पूर्व ये महाशय हरिजन एक्ट में भी बुक हुए थे; उस वक्त करीब साढे तीन लाख नकद देकर जान छुड़ाई थी।

विधायक महोदया बेशक इन भगौड़ों के भागने से आज परेशान हों जो कि स्वाभाविक भी है। लेकिन इसके लिये असल दोषी भी तो खुद विधायक महोदया ही हैं। बेशक विधायक ने अपना बनाने के लिये इन्हें लूटने खाने की खुली छूट एवं पूरा संरक्षण दिया हो; लेकिन वही मुंहलगी लूट आज इनके भागने का कारण भी है। इनकी आदतें अब इतनी बिगड़ चुकी हैं कि ये सत्ता से बाहर सांस भी नहीं ले सकते। इनके तमाम अवैध धंधे पल भर में धराशाही हो सकते है। इन सब को बचाने के लिये सत्ता की छाया में रहना इनकी मजबूरी है; इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की सत्ता अब चंद दिनों की है, यह सबको नज़र आ ही रहा है।

अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसे सत्तालोलूप एवं भ्रष्टाचारियों को अपने यहां पनाह देकर भाजपा किस आदर्शवाद का संदेश जनता को देना चाहती है?

ख़बर दार

मोदी के 'लोकतंत्र' में मजबूत होता लूटतंत्र

मजदूर मोर्चा ब्यूरो

नरेन्द्र भाई मोदी ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ के वक्त जो तमाम वायदे किये उनमें 'मजबूत सरकार के दम पर मजबूत लोकतंत्र' का दावा बार-बार दोहराया गया। मोदी का कहना था कि अगर केन्द्र में एक मजबूत सरकार होगी तो देश की सीमा पर खड़ा सैनिक भी मजबूत होगा, देश के भीतर आम आदमी भी मजबूत होगा और अन्तर्राष्ट्रीय बिरादरी में भारत की आवाज भी मजबूत होगी।

जबकि प्रधानमंत्री के रूप में एक माह से अधिक का मोदी-शासन में एकमात्र मजबूत होने वाला वर्ग है पूंजीशाहों का। इस वर्ग को मजबूत करने में मोदी के नेतृत्व में नौकरशाहों और अर्थशास्त्रियों की पूरी फ़ौज लगी देखी जा सकती है। मोदी की भाजपा को और उसके तमाम राजनेताओं को भी इसी लाइन पर चलते देखा जा सकता है।

पूंजीशाहों की बढती समृद्धि का एक पैमाना देश का शेयर बाज़ार होता है मोदी के सत्तानशीन होते ही इस बाज़ार में पूंजीशाहों के लिए ऐसी अनुकूल लहर चली कि सूचकांक कुलांचे भरता हुआ सारे रिकार्ड तोड़ने लगा। अनुमान है कि बैठे-बिठाये पूंजीशाहों की शेयर बाज़ार में रकम 20 प्रतिशत तक बढ गयी।

इसके बरक्स आम आदमी का क्या हुआ?

उसके लिए महंगाई 20 प्रतिशत तक बढ गयी। कयास है कि शेयर बाजार भी चढता जायेगा और महंगाई भी बढती जायेगी।

प्रधानमंत्री बनकर मोदी को अपना असली चेहरा छिपाने की जरूरत नहीं रह गयी है। अब वह सरेआम कहने में भी संकोच नहीं कर रहा कि सरकार कड़े कदम उठायेगी और जनता को इसके लिए तैयार रहना चाहिये। इस अभियान में रेल का किराया-भाड़ा बढ़ाने के अलावा, गैस तेल, अनाज, सब्जी, दूध इत्यादि रोजमर्रा की जरूरतें महंगी होने जा रही हैं। चिकित्सा, मकान, रोजगार तो पहले से भी ज्यादा दुर्लभ करने की ओर कदम उठाये जा रहे हैं।

सवाल है कि सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कड़े कदमों का बोझ प्रधानमंत्री मोदी आम जनता पर ही क्यों डाल रहे हैं। यानी लूटतंत्र तो ज्यों का त्यों कायम है पर लोकतंत्र के नाम पर आम लोग़ों को पीसने का दायित्व मोदी सरकार बखूबी निभा रही है। कहा जा रहा है कि किसानों व ग़रीबों को मिलने वाली तमाम सब्सिडी को कम या समाप्त किया जायेगा। इस सब्सिडी से कहीं अधिक सब्सिडी (चार लाख करोड़ रुपये सालाना) कार्पोरेट वर्ग को दी जाती है। इसे समाप्त करने की बात तक नहीं की जा रही। जबकि इसे खत्म करने के बाद ग़रीबों को दी जाने वाली सब्सिडी को छूने की भी जरूरत नहीं होगी। मोदी के इन असली यारों को भला कौन छेड़ने की हिम्मत कर सकता है?

लूटतंत्र के सबसे बड़े दो हथियार आते हैं-भ्रष्टाचार व कालाधन। मोदी राज आने पर यदि किसी ने सोचा हो कि इन हथियारों को नष्ट किया जायेगा तो मोदी के पास उसे देने को निराशा के सिवाय और कुछ नहीं है।

रोजमर्रा के जीवन का भ्रष्टाचार अपनी गति से चल रहा है और कालाधन दिन दूना रात चौगुणा बढ रहा है। मोदी की मजबूत सरकार बनाने का जनता को यही फल मिला है।

दरअसल देश के आम नागरिक को देने के लिये मोदी के पास और कुछ है भी नहीं। कांग्रेस की मनमोहन सरकार में बड़े घोटलों का भंडाफ़ोड़ दूसरे कार्यकाल में होना शुरू हुआ। मोदी की भाजपा सरकार में पहले महीने से ही शुरूआत हो गयी है। मध्यप्रदेश का जून 2014 में उजागर हुआ व्यापम घोटाला कांग्रेसी सरकारों के घोटलों से इक्कीस ही ठहरेगा। युवाओं की आंखों में सरकार धूल झोंक कर मेडिकल सहित तमाम व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में दाखिले वर्षों तक पैसे और प्रभाव के दम पर बेचे-खरीदे गये हैं।

अभी तो आग़ाज़ हुआ है। ज्यों-ज्यों लूटतंत्र मजबूत होता जायेगा त्यों-त्यों घोटालों का आकार भी बढता जायेगा। बेशक मोदी फ़िर भी लोकतंत्र की ही दुहाई देते रहेंगे। क्योंकि मोदी का 'सुशासन' कांग्रेसियों के मुकाबले अधिक व्यवस्थित होता है, लिहाजा यह लूटतंत्र भी कहीं अधिक व्यवस्थित होगा। मसलन दिल्ली में बिजली कटौती की खुली छूट देकर बिजली कम्पनियों द्वारा बिजली मंहगी करने की ज़मीन तैयार कर दी गयी है। इसी तरह रेल सेवा को भी विश्वस्तरीय बनाने के नाम पर आम आदमी की जेब पर डाका डाल दिया गया है। सरकार की शह से अम्बानी जैसे पूंजीशाह ताल ठोंक कर कह रहे हैं कि गैस को मंहगा करना ही पड़ेगा।

इस लूटतन्त्र में पिसती जनता के पास विकल्प क्या है? यही कि लोकतन्त्र के नाम पर अगले 5 वर्ष तक मोदी उसे ठगता रहे।

महाबली मोदी!

इराक गृह-युद्ध में 10 000भारतीय फंसे हुए हैं। उन्हें प्रतीक्षा है कि कब महाबली मोदी 'सुपरमैन' के अवतार में अवतरित होंगे और उन्हें साक्षात मौत के मुंह से निकाल कर सुरक्षित वापस भारत ले जायेंगे।

पाठक भूले नहीं होंगे कि साल भर पहले जून 2013 में उत्तराखंड की त्रासदी में फंसे 6000 गुजरातियों को एक दिन में निकाल कर सुरक्षित गुजरात ले जाने का दावा मोदी ने किया था। तब मोदी गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री होते थे और उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा में लाखों लोग जगह-जगह बाढ व भू-स्खलन में फंसे पड़े थे। सारा यातायात एवं संचार अस्त-व्यस्त हो गया था। फ़िर भी वायु मार्ग से देहरादून पहुंच कर वातानुकूलित वातावरण में मोदी ने प्रेस कांन्फ्रेंस की और उपरोक्त बेशर्मी भरा दावा कर डाला।

इराक की स्थिति उत्तराखंड जैसी ही विकट है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि यहां मुकाबला प्रकृति के हमलों से न होकर आतंकियों के हमलों से है। पर, अब मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके पास लाखों का सैन्य बल है। वायुसेना और नौ सेना के साथ-साथ कूटनीति की सुविधा भी है। ऐसे में यदि इराक में फंसे भारतीय और उनके भारत में रह रहे परिजन मोदी से सुपरमैनी दिखाने की उम्मीद कर रहे हों तो यह स्वाभाविक ही कहा जायेगा।

यह अलग बात है कि महाबली फ़िलहाल दुबक कर प्रधानमंत्री कार्यालय की शानदार ऐय्याशियों को भोगने में व्यस्त हैं। कहने को विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज की मार्फ़त परिजनों को सांत्वना दी जा चुकी है, और कूटनीतिक पहल के नाम पर पिछली इराक त्रासदी के समय बगदाद में भारत के राजदूत रहे रेड्डी को पुन: बगदाद भेज दिया गया है। विशेष कंट्रोलरूम और क्राइसिस समूह को भी तस्वीर में उतारा गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवल ने भी प्रधानमंत्री कार्यालय में अपना खेमा लगा लिया है।

यह सारी कवायद जानी पहचानी सी नहीं लगती? केन्द्र की कोई भी सरकार यही सब तो करती आई है। लोग तो यह जानना चाहते हैं कि महाबली मोदी ने अलग से क्या किया? जब इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा से 6000 लोग़ों को उन्होंने एक दिन में निकाल लिया तो सैनिक आपदा से 10 000 लोग़ों को निकालने में कोई प्रगति क्यों नहीं हो रही?

महाबली मोदी को तो यह काम दो दिन में सम्पन्न कर देना चाहिये था। और कुछ नहीं तो जैसे उत्तराखंड में फ़ंसे लोग़ों को लेकर मोदी ने जैसे पाखंडपूर्ण दावे किये थे, वैसे ही दावे इराक में फ़ंसे लोग़ों को लेकर भी वे आज नहीं तो कल करेंगे ही। महाबली का लबादा धीरे-धीरे उतरना शुरू हो गया है।

-आनंद कुमार